(d) if so, what steps have been taken by Government to remove this mismanagement?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI SUKHBIR SINGH BADAL): (a) Yerraguntla unit of CCI has been sold to M/s. India Cement Limited (ICL) at a cost of Rs. 200.70 cr. on open tender basis and physical possession was handed over on 21.1.98. Three other units vis. Charkhi Dadri, Mandhar and Akaltara which had been identified by the BIFR in the Draft Rehabilitation Scheme circulated by them, are proposed to be sold.

(b) If the proposed sale of 3 Units materializes, 7 units i.e. Bokajan, Rajban, Tandur, Kurkunta, Adilabad, Nayagaon and Nayagaon Expansion including Delhi Grinding Unit will remain with CCI.

(c) and (d) Most of the units of CCI have become sick due to various reasons resulting in continuous losses and BIFR is already seized of the problem of rehabilitating the Company.

खादी उद्योग द्वारा डेनिस जींस का उत्पादन

2995. **श्री रमा शंकर कौशिक:** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खादी उद्योग नई पीढ़ी में खादी की लोकप्रियता बढ़ाने की दृष्टि से डेनिम जींस का उत्पादन करने पर विचार कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त): (क) जी, हां। खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग ने हाल ही में एक नया कपड़ा यानी "डेनिम कपड़ा" निकाला है।

(ख) ग्राहकों को नये उत्पाद की पेशकश करने के इरादे से खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग ने हाथ से कताई किए गए धागे का प्रयोग करके हाथ से बुने हुए खादी के डेनिम कपड़े का विकास किया है। लोगों को इस विकास के बारे में जानकारी देने तथा खादी उत्पादनकारी एजेंसियों को डेनिम का उत्पादन आरंभ करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु "स्वदेशी मेले" में यह बुनाई प्रौद्योगिकी प्रदर्शित की गयी थी। सतत् उत्पादन पद्धति बनाने के उद्देश्य से सात संस्थाओं को वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ करने के लिए चुना गया है जिनमें से प्रत्येक के लिए प्रति वर्ष 2000 मीटर प्रारंभिक लक्ष्य रखा गया है। यह उत्पादन 2 अक्तूबर, 1999 को आरंभ किए जाने की आशा है।

उत्तर प्रदेश में जूता उत्पादकों को सहायता

2996. **श्री मनोहर कान्त ध्यानी:** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में जूता उत्पादकों को सहायता प्रदान करने की दृष्टि से यू०एन०डी०पी० के अंतर्गत केन्द्र सरकार को स्वीकृत 48.00 करोड़ रुपए की धनराशि में से 45.00 करोड़ रुपए की मांग की है;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय उद्योग विकास कार्यक्रम के द्वितीय चरण के लिए उत्तर प्रदेश को विशेष महत्व प्रदान करते हुए केन्द्र सरकार के अंश के रूप में 22.50 करोड़ रुपए प्रदान किए जाने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ग) यदि हां, तो राज्य के जूता निर्माताओं को प्रोत्साहन देने के प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति प्रदान कर दी जाएगी; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त): (क) से (ग) उत्तर प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय चमड़ा विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 45 करोड़ रुपए की स्वीकृति के लिए जून 1998 में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। तब से दिसम्बर, 1999 तक आगरा तथा कानपुर के पादुका (फुटवियर) कारीगरों को सहायता प्रदान करने के लिए और कानपुर स्थित जीनसाजी क्षेत्र की सहायता हेतु राष्ट्रीय चमड़ा विकास कार्यक्रम के दूसरे चरण के अंतर्गत 256,000 अमरीकी डालर की रकम आबंटित की गई है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

TRIPS agreement

2997. DR. MAHESH CHANDRA SHARMA: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether it is a fact that TRIP's Agreement allows examination of product

patents applications from the date of application of TRIPs Agreement i.e. from 1st January, 2000;

(b) if so, the reasons for providing in the ordinance to keep the patent applications pending till 31st December, 2004; and

(c) whether his Ministry will place a copy of List of Applications received for product patents?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI SIKANDER BAKHT): (a) and (b) As a developing country member of the World Trade Organisation, India has a transition period upto 31st Dec., 1999 to align its laws on intellectual property rights in accordance with its obligations under the Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) of the World Trade Organisation Agreement. An additional transition period, upto 31 December, 2004, is also available to introduce product patent protection to areas of technology not protected so far, mainly in relation to pharmaceuticals and agricultural chemicals. It can thus delay the examination of product patent applications filed in the fields of pharmaceutical and agricultural chemicals upto 31 December, 2004.

(c) All applications received for patents, whether product or process, are notified in the Gazette of India Part III Section (ii).

Assets and liablities of PSUs

2998. SHRI C.O. POULOSE: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state the assets and liablities of National Instruments Limited (NIL), Bharat Opthalmic Glass Ltd., (BOGL), Weighbird India Ltd. (WIL), National Bicycle Corporation of India Ltd., Cycle Corporation of India Ltd., (CCIL) Mining & Allied Machinery Corporation (MAMC), Tannery & Footwear Corporation Ltd. (TAFCO), and Rehabilitation India Corporation Ltd. (RIC) separately?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI SUKHBIR SINGH BADAL): A statement of assets and liabilities is given below:

(Rs. in Crores)

Sl. No.	Name of PSUs	(As on 31.3.1998) Assets*		@Liabilities
		Fixed	Current	
1.	National Instruments Ltd. (NIL)	1.44	4.95	164.97
2.	Bharat Opthalmic Glass Ltd. (BOGL)	1.06	7.81	185.46
3.	Weighbird India Ltd. (WIL)	0.06	0.87	36.51
4.	National Bicycle Corporation of India Ltd. (NBCIL)	0.67	5.87	168.17
5.	Cycle Corporation of India Ltd. (CCIL)	0.37	5.50	396.44
6.	Mining & Allied Machinery Corporation Ltd. (MAMC)	20.10	73.84	189.28
7.	Tannery & Footwear Corporation of India Ltd. (TAFCO)	3.58	2.72	297.59
8.	Rehabilitation Industries Corporation Ltd. (RIC)	1.21	11.45	468.31

*Excluding Accumulated losses
@ Based on annual accounts